प्रारुप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1 (For linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District -Uttarkashi

No--- 153

Dated____23 |11 | 2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.09 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of UPCL (name of user agency) for Elecrification work (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Kunara-Ludrala in Mori Tehsils.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.09 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl: As above.

Signature (Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT- UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Chauhan, I.A.S District Collector Uttarkashi on Dated 23/11/2017 at time 11.00 PM in which application claiming rights in Kunara-Ludrala area measuring 2.09 hect. for the electrification work of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

District Collector
Chairman- District Level
Committee

It is further certified that-minuts of Meeting of electrification work in village Kunara-Ludrala. Regarding FRA is as following.

S. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had carried out for the enteir 2.09 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee(s) Sub Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as requires under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Nagar Palika Parishad has given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of electrification work is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre agricultural communities	

जिला पंचायत सदस्य ग्राम कुनारा-लुदराला

जिला समाज कत्याण अधिकारी जिला संतुर्तारकाशीाय अधिकारी उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी टोंस वन प्रभाग, पुरोला जिलाधिकारी उत्तरकाशी

रोन्स् वन प्रभाग, परोला

सिंगतूर रेंज टौंस वन प्रमाग, पुर्ह्ता

टीन्स वन प्रभाग, पुरोला

उत्तरकाशी

परियोजना का नाम -

जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम-कुनारा-लुदराला के विद्युतीकरण का कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कुनारा-लुदराला के विद्युतीकरण कार्य हेतु (1.89 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.20 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, निजी भूमि शून्य हे0 अर्थात कुल 2.09 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-मोरी) की दिनांक 10/19/12 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एम प्रमा नेजी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- श्री एमः एमः ने अ उपजिलाधिकारी
- श्री उनार ० रून ० श्रीनास्त न उप प्रभागीय वनाधिकारी
- श्री पवन पवाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी कि विवस्त माज कल्याण अधिकारी कि विवस्त माज कल्याण अधिकारी विवस्त माज कल्याण अधिकारी
- श्रीमती बाल्नेमारी बीठडी०सी० क्षेत्र

पांखरी (मार्ज उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उम्र जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम कुनारा-लुदराला के विद्युतीकरण कार्य हेतु 2.09 हे0 आरक्षित वन भूमि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतू प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कुनारा—लुदराला के विद्युतीकरण कार्य हेतु 2.09 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

(a) 3

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- <u>सार</u> जनपद <u>उत्यक्ष</u>

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी,को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील गाँग

प्रारुप-30.3

परियोजना का नाम – जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम-कुनारा-लुदराला के विद्युतीकरण का कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-कुनारा-लुदराला तहसील-मोरी, जिला-उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के निर्माण हेतु (1.89 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.20 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) निज़ी भूमि शून्य हे0 अर्थात कुल 2.09 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुनारा—लुदराला द्वारा दिनांक 134.16.को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुनारा—लुदराला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2.09 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्रामक्सचिवखण्ड मो

मुहर सहित

ह0/-ग्राम प्रधान/सरपंच मृहर सहिती

बीमती लायवरी वैश

धाम पंचायत क्नासः,

विकास खण्ड मारी(उन

प्रारुप-30.4

दिनांक १३/१०/१५को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायतकुन्नानी

कमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	श्रीजेन्द्र सिंह रागा	र छेड विर
62	निनेश ४१०११	विनेश राजा
03	<u> क्रीरपाल</u>	-सुरपाल
64	37Raice	Ain
05	20/1 FASE 2701	2012 1822
06	- थुड्फ्वीर	अरत सिंह
67	-अरत सिंहं	
08	इकम सिहं	ATM COL
09	चीवार सिंह	सेनार । सिह
10	छपर सिर्ट शना	2017 (A22011
1)	हाकम सिंह राजा	area care
12	51012 HE 21011	भगत पह
13	श्राज्ञे हैं।	र प्रिश
14	न्त्रें)	नरेश

ह0/-ग्राम प्रधान अधान भूगा यहाँ वेमती साव्यत के ग्राम पचायत-कुनारा विकास खण्ड-मोरी(उर